उदारीकरण निजीकरण एवं भूमंडलीकरण का शिक्षा पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. राजेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र
श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया

शोध सार

अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एल.पी.जी. अर्थात उदारीकरण,निजीकरण तथा वैश्वीकरण को भारत सरकार द्वारा 1991 में अपनाया गया।उदारीकरण में सरकारी नियंत्रण को ढीला करना,निजीकरण में निजी संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा भूमंडलीकरण में वैश्विक सहयोग को स्वीकार किया गया है।पश्चिमी देशों में पनपा यह पौधा धीरे-धीरे भारत की भूमि में पल्लवित और पोषित हो रहा है।आर्थिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र के यह सुधारों से शिक्षा भी अछूती नहीं है।उदारीकरण की नीति के कारण आज स्वायत्त शैक्षिक संस्थानों की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है।निजीकरण उपलब्ध संसाधनों के साथ अन्य विकल्पों के द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में एक कदम है।वैश्वीकरण में विश्व के ज्ञान विज्ञान से परस्पर सहयोग से आगे बढ़ाना है।परंतु भारतीय प्रवेश के आधार पर उक्त तीनों नीतियों का विवेकपूर्ण उपयोग अपेक्षित है

परिचय

भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई सन 1991 को एक आर्थिक नीति के तौर पर एल.पी.जी.(उदारीकरण निजीकरण तथा वैश्वीकरण) की घोषणा की गई।इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था संक्षेप में उदारीकरण सरकारी प्रतिबंधों को कम करना तथा निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवसायों को निजी क्षेत्र हेतु खोलने तथा भूमंडलीकरण में व्यापार एवं निवेश को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया गया है।इस आर्थिक नीति ने शिक्षा को भी प्रभावित किया है।मुक्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा ने इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है।

उदारीकरण का शिक्षा पर प्रभाव

उदारीकरण में सरकारी नियंत्रण से पूर्ण या आंशिक शिथिलता प्रदान की जाती है।उदारीकरण में स्वतंत्रता का भाव निहित होता है।इसमें विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होता है।उदारवाद ने ही अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति का स्वतंत्रता पूर्वक मार्ग प्रशस्त किया है।आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण जहां मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है,वहीं राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाता है।उदारीकरण के फलस्वरुप शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है।उदारीकरण ने शिक्षा के अर्थ, स्वरूप,उद्देश्य,पाठ्यक्रम आदि सभी क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।शिक्षा में उदारीकरण से शैक्षिक नियोजन उसके कार्यान्वयन में अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्ति मिली है।संस्थाएं अपनी आवश्यकता अनुकूल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।यह सिद्धांत सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र

में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो समाज के वंचित वर्गों तथा महिलाओं,निर्धन आदि की शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। मुक्त शिक्षा,दूरस्थ शिक्षा,विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग,बाल केंद्रित शिक्षा आदि ऐसी प्रवृत्तियां हैं,जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उदारीकरण का परिणाम कहीं जा सकती है।उदारीकरण क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पुष्ट करने का साधन है।इसे केवल मानकों में छूट के रूप में नहीं मानना चाहिए,बल्कि इसका प्रयोग शिक्षा को बेहतर बनाने में किया जाना चाहिए।

निजीकरण का शिक्षा पर प्रभाव

भारत में आर्थिक क्षेत्र में निजीकरण की शुरुआत 1991 से देखी जा सकती है।पश्चिमी देशों से होने वाले इस आर्थिक सुधार से भारत भी अछूता नहीं रह सका है।आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ शिक्षा के लिए निजीकरण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। निजीकरण के पूर्व संस्था के संचालन एवं प्रबंधन का समस्त दायित्व सरकार के पास सीमित थे। परंतु विभिन्न आर्थिक,राजनीतिक कारणों से यह अधिकार विकेंद्रित करने पड़े।निजीकरण सरकारी उत्तरदायित्वों के बोझ को कम करने का एक तरीका है।जिसमें बेहतर विकास के लिए जन भागीदारी के द्वारा खोले हैं।निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।लागत में कमी आती है तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है हालांकि भारत में पूर्ण निजीकरण को न अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है।जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों की भागीदारी को स्वीकार किया गया है भारत जैसे असीमित जनसंख्या वाले देश के लिए सार्वभौमिक शिक्षा के लिए केवल सरकारी प्रयास नाकाफी है।पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक निजीकरण तेजी से पैर पसार रहा है। स्ववित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों का जाल यात्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ है 90 के दशक से पूर्व जहां शिक्षा सर्वसुलभ नहीं थी।संस्थाएं कम थी,प्रवेश की इच्छुक छात्र अधिक थे परंतु निजीकरण की फलस्वरुप आज की स्थिति बिलकुल उलट है कई संस्थाओं को छात्र ढूंढे नहीं मिल रहे हैं।चिकित्सा,प्रौद्योगिकी प्रबंधन आदि भी निजीकरण से अछूते नहीं है।

निजीकरण से लाभ और हानि दोनों है।लाभ पर दृष्टिपात करें तो व्यापक संख्या में शिक्षा संस्थाएं होने के कारण छात्रों को अध्ययन के अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।इसके साथ-साथ प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है।आज अनेक ऐसे निजी संस्थान है,जो वैश्विक गुणवत्ता युक्त शिक्षा की प्रसार में संलग्न है।सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण निजीकरण आज की अनिवार्य आवश्यकता है।परंतु दूसरे पहलू पर विचार करें,तो निजीकरण में अभिभावकों के आर्थिक शोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी है।जो स्तरीय शैक्षिक संस्थाएं हैं वहां फीस की दर बहुत उच्च है।जिसने अभिभावकों का बजट बिगाड़ रखा है।गरीब परिवार के लिए यह शिक्षा दूर की कौड़ी है,और ग्रामीण क्षेत्र की निजी संस्थाएं स्तरहीन हैं।जो संसाधन अभाव से जूझ रही है।जहां न्यूनतम सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को अल्प वेतन में अपनी सेवाएं देनी पड़ रही है। जिससे न केवल उनका शोषण हो रहा है,बल्कि बेरोजगारी भी बनी हुई है।प्रजातंत्र में नागरिकों की शिक्षा की जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती है।इसलिए आज आवश्यकता है,कि निजीकरण के दोषों को दूर किया जाए तथा सर्वसुलभ गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए।जिसमें निजी संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए तथा गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का उत्तरदायित्व सरकार पर है।

भूमंडलीकरण का शिक्षा पर प्रभाव

आज वैश्वीकरण का युग है।कोई भी देश सभी संसाधनों से परिपूर्ण नहीं है। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं।इसमें विभिन्न राष्ट्र अपने क्रियाकलापों में अन्य देशों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।तथा एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हैं।भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का विचार हजारों वर्षों पूर्व से ही समाहित है।भूमंडलीकरण ने आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र के अतिरिक्त शिक्षा को भी प्रभावित किया है।अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता इसका एक ज्वलंत उदाहरण है इसने भारतीय पुरातन संस्कृति पर निश्चय ही कुठाराघात किया है।परंतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वैश्विक स्तर की शिक्षा संस्थाएं देखने को मिली है।भारतीय

छात्रों ने अपनी योग्यता की धाक पूरे विश्व में जमाई है। भूमंडलीकरण ने आज हमारे शिक्षा के स्वरूप में बड़े सकारात्मक परिवर्तन किए हैं।सूचना एवं संप्रेषण की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हो रहा है।जिससे भारत विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है।हम घर बैठे वैश्विक ज्ञान विज्ञान पढ़कर उससे लाभान्वित हो रहे हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है,कि भारतीय परिस्थितियों में उदारीकरण,निजीकरण एवं वैश्वीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है।परंतु उससे होने वाली हानियों से बचने का उपाय भी किया जाना चाहिए।हमें एल.पी.जी का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन करना है, पश्चिमी देशों का अंधानुकरण नहीं।

संदर्भ

1-भारतीय शिक्षा का इतिहास,विकास एवं समस्याएं गुप्ता,एस.पी डॉ. अलका गुप्ता,शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद 2015

2-शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियां, योगेंद्रजीत,भाई,अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।

3- https//hi.wikipedia.org

4- https//plutuseducation.com

Contributors Details:

डॉ. राजेश कुमार